

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
सांख्यिक विभाग, नई दिल्ली

प्रमुख,
श्री अशोक प्रसाद,
नियोजक,
सांख्यिक विभाग, भारत, रांची

दिनांक,
राज्य,
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 21 जून, 2003

विषय: भारत सरकार के अन्तर्गत संघीयता निजी विद्यार्थियों को सम्बन्धित
केतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट करने के संबंध में।

संक्षेप, निम्नानुसार कक्षा के वि मानव संसाधन विकास विभाग, भारत
सरकार के द्वारा विद्यार्थीपरान्त सी०बी०एस०ई० से सम्बन्धित केतु एकीकृत
स्थापना, आरात्मिक प्रभावित क्षेत्र के लिए निर्धारित जहाँ एवं अन्यथा
के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है:-

1- विद्यार्थी की वार्षिक कक्षा आय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं
हो सके कि प्रमाणित हो सके कि विद्यार्थी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से
स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो कक्षा होगी उच्च
उपयोग की विद्यार्थी के विकास में किया जायेगा । विद्यार्थी में अर्जित सभी
कर्तव्यों को का से का राज्य सरकार में कार्यरत कक्षा कर्तव्यों के क्षेत्र विज्ञान एवं
अन्य के परामर्श सुझाव करना होगा ।

2- विद्यार्थी को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

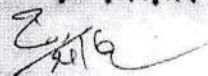
3- विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़
निर्धारित भूमि संबंधी सरकार की जमीन को संबंधित जमाने हुए दोनों क्षेत्र के लिए
समान लय से का से का दो एकड़ भूमि विद्यार्थी के नाम से निर्दिष्ट या 30 वर्षों
से निर्दिष्ट पट्टा/ लीज पर होना चाहिए ।

4- विद्यार्थी में विन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी ।

5- नामांकित केतु कि ती प्रकार छोटेका या केपिटेकन कीत नहीं
लिया जायेगा ।

6- ग्रामीण क्षेत्र के नीचे परिवार के जहाँ का निःशुल्क । प्रविष्टा
नामांकित के लिए स्थान मुहैया होगा ।

7- विद्यार्थी का कार्यवाहक सम्बन्धित में होना चाहिए ।



विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का तैयार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान धर्म, शारीरिक एवं व्यक्तिगत विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा।

8-विद्यालय में छात्र/छात्राओं की समुचित संख्या एवं उनके अनुपात में शिक्षण होना चाहिए।

9.-विद्यालय में नागरिक प्रवृत्तियाँ, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रविष्टि आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीनपरान्त संशोधन कर लेगी।

10.- विद्यालय संयोजन हेतु गठित विकासकमी के आधार पर गठित शासकीय विद्यालय के सदस्यों की कार्यवाही पूर्ण होने पर नये सदस्यों की तृतीयांश विद्या पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में पेश करना होगा।

11.- राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एल-सेन्स प्रोग्राम तथा एनएसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाईड की सुवार्द्धता से करना होगा।

12-यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बन्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-2-01 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के अधीन सुरक्षित होगा।

13.-अनुज्ञित शर्तों या बन्धनों के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14.-अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये विद्यालय द्वारा तय/कागजातों/अभिलेखों को वाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न न पाया जाय वा विद्यालय द्वारा राष्ट्र वा राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो वा ऐसा कार्य किसी वास्तविक कठूता फैलाता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

15.-विद्यालय द्वारा अनुज्ञित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सहाय पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं एकादेशीय अधिकारिताओं की जाँच करा लेगी और बाँधोपरान्त अनुसूची कारवाही कर लेगी।

16.- एतद्विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निबटारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17.- समय-समय पर लोकोचित में सरकार द्वारा विद्यालयसम्बन्धन

संबंधी जो निर्णय लिये जाते, उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शांति के अभाव मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

विद्ययातभाजन,

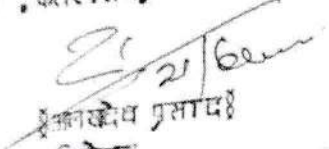
EO/-
[अनखेदम प्रसाद]

निदेशक,

[माध्यमिक शिक्षा] शारदा
राँची

ज्ञापांक _____ राँची, दिनांक _____

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय उप शिक्षानिदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/प्राचार्य, डोली मदर्स एकादमी, क्लारासगढ़ धनबाद को संपन्नार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।


[अनखेदम प्रसाद]
निदेशक,
[माध्यमिक शिक्षा] शारदा, हजारी
राँची।